भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1832
दिनांक 05 दिसंबर, 2024

पेट्रोल और डीजल पर कर

†1832. श्री जिया उर रहमान :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पेट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय और राज्यस्तरीय करों को कम करने का विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी सिलेंडर वितरण की समस्याओं के समाधान के लिए कोई नीति है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या यह नीति अपनाई गई है; और
(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): केन्द्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में 4 नवंबर, 2021 से क्रमश: 5 रुपए/लीटर और 10 रुपए/लीटर तथा 22 मई, 2022 में क्रमश: 8 रुपए/लीटर और 6 रुपए/लीटर की कमी की है, जो उपभोक्ताओं को पूर्णतः प्रदान की गई थी। कतिपय राज्य सरकारों ने भी नागरिकों को राहत पहुँचाने के निमित्त राज्य वैट दरों को कम कर दिया था। मार्च, 2024 में ओएमसीज ने भी पूरे देश में पेट्रोल और डीजल, प्रत्येक के खुदरा मूल्यों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की थी।जिसके परिणामस्वरुप, पेट्रोल तथा डीजल के मूल्य घटकर नवंबर 2024 में क्रमशः 94.77 रुपए प्रति लीटर और 87.67 रुपए प्रति लीटर हो गए।

भारत सरकार ने आम नागरिको को उच्च अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों से सुरक्षित रखने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए हैं, जिनमें कच्चे तेल की आयात बास्केट में विविधता लाना, घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व के प्रावधानों को लागू करना, पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण बढ़ाना आदि शामिल है।

हाल ही में पीएसयू ओएमसीज ने अंतर-राज्य भाड़े का युक्तिकरण किया है। इससे राज्यों के भीतर सुदूर भागों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के रुप में पेट्रोलियम ऑयल और ल्यूब्रिकेंट (पोओएल) डिपो से दूर,सुदूर स्थानों में रहने वाले उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। इस पहल ने राज्य में पेट्रोल या डीजल के अधिकतम और न्यूनतम खुदरा मूल्यों के अंतर को भी कम कर दिया है।

(ख)से (ङ): एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स की नियुक्ति एक सतत प्रक्रिया है और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स की स्थापना के लिए स्थलों की पहचान बिक्री संभाव्यता आधारित पर होती है जो उनको वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाती है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) देश भर में नयी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स की स्थापना करके ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी की पहुँच को बढ़ाने में कार्यरत हैं। दिनांक 01.11.2024 की स्थिति के अनुसार, देश भर में 25,532 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स हैं जिसमें से 17,610 डिस्ट्रीब्यूटर्स ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, ओएमसीज ने पूरे देश में 01.04.2016 से 31.10.2014 की अवधि के दौरान 7944 डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स की स्थापना की है जिसमें से 7361 (93%) ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान कर रही हैं।

उपरोक्त के अलावा, नए कनेक्शन के लिए नामांकन, रीफिल बुकिंग और रीफिल की डिलीवरी जैसी विभिन्न एलपीजी से संबंधित सेवाओं के लिए सीएससी वीएलई (ग्रामीण स्तरीय उद्यमियों) नेटवर्क का लाभ प्राप्त करने हेतु ओएमसीज ने सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी एसपीवी) के साथ करार किया है।

***